

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून दिनांक 07, जून, 2010

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए सहकारी सहभागिता योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:-134/नियो0/सहभागिता/2010-11 दिनांक 07 अप्रैल, 2010 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-187/XXVII (1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए सहकारी सहभागिता योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण/दीर्घकालीन ऋण/आवास ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष भारत सरकार/नाबार्ड से नियमानुसार प्रतिपूर्ति के पश्चात राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किये जाने वाले ब्याज दरों के उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) उक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 519/XIV-1/2008 दिनांक 22 जुलाई 2008 में उल्लिखित शर्तों/विवरण के अनुसार ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश हेतु सहकारी संस्थाओं से प्राप्त क्लेम के निबन्धक स्तर से सम्यक परीक्षण एवं त्रैमासिक प्रगति समीक्षा उपरान्त सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वीकृति की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा एवं अग्रिम भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना से महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व बाउचर संख्या लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड का होगा।

(3) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-187/XXVII (1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल इसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज के राज्यांश के अनुदान के रूप में ही प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा किसी ऐसे मद पर धनराशि व्यय न की जाय, जो योजना में स्वीकृत नहीं है।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा, तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न की जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/समक्ष अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय।

(8) उक्त योजना का निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2011 तक व्यय सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करायेंगे तथा अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2011 को शासन को समर्पित की जाय।

(9) गत वित्तीय वर्ष में लाभान्वित तथा चालू वित्तीय वर्ष हेतु चिन्हित/सम्भावित लाभार्थियों का विवरण समाज कल्याण विभाग तथा शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या:-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2425-सहकारिता-आयोजनागत-00-796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना-05-सहकारी सहभागिता योजना-00- 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग के अशा0- संख्या:-99 (P)/XXVII-4/ दिनांक 31 मई, 2010 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या:-996/XIV-1/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी संघ लि0, देहरादून।
7. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेंद्र पाल सिंह)
अनुसचिव।